

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	आश्विन 05, सोमवार, शाके 1943-सितम्बर 27, 2021 <i>Asvina 05, Monday, Saka 1943- September 27, 2021</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**  
**(GROUP-II)**  
**NOTIFICATION**

**Jaipur, September 27, 2021**

**No. F. 2(21)Vidhi/2/2021.-** The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 25<sup>th</sup> day of September, 2021 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, 2021**

**(Act No. 11 of 2021)**

(Received the assent of the Governor on the 25<sup>th</sup> day of September, 2021)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 98, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** In section 98 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (2), for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(ii) after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that on resumption of land granted under sub-section (1), the revenue officer not below the rank of a Tehsildar finds that contravention of provisions of this section or rules made thereunder is of such nature that has rendered the land of no use except for residential purpose, he may, with the prior approval of the State Government, allot such land to the person to whom it has been granted, upon

payment of premium therefor at the rate fixed under section 96 and on payment of penalty as may be prescribed.”.

**3. Amendment of section 261, Rajasthan Act No. 15 of 1956.-** After the existing clause (xv) and before the existing clause (xvi) of sub-section (2) of section 261 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:-

“(xv-a) prescribing under proviso to sub-section (2) of section 98, penalty to be paid by the person to whom the land has been granted and who is found guilty of contravention of the section;”.

विनोद कुमार भारवानी,  
Principal Secretary to the Government.

### विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2021

**संख्या प.2(21)विधि/2/2021.-** राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2021 (एक्ट नं. 11 ऑफ 2021)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2021**

(2021 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 98 का संशोधन.-** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 98 में,-

(i) उप-धारा (2) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु उप-धारा (1) के अधीन अनुदत्त भूमि के पुनर्गृहीत किये जाने पर राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के पद का न हो, यह पाता है कि इस धारा या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन ऐसी प्रकृति का है जिससे कि वह भूमि, निवासीय प्रयोजन के सिवाय, अनुपयोगी हो गयी है तो वह, ऐसी भूमि को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धारा 96 के अधीन उसके लिए नियत की गयी दर पर प्रीमियम का संदाय किये जाने पर और शास्ति, जो विहित की जाये, का संदाय किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को, जिसे यह अनुदत्त की गयी है, आबंटित कर सकेगा।"

**3. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 261 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड [15] के पश्चात् और विद्यमान खण्ड [16] से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"[15-क] धारा 98 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अधीन, व्यक्ति जिसे भूमि अनुदत्त की गयी है और जिसे उस धारा के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, द्वारा संदत्त की जाने वाली शास्ति विहित करने के लिए;"।

विनोद कुमार भारवानी,  
प्रमुख शासन सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।